Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding development of flood safety measures in flood-prone districts of Assam -laid.

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): हम बड़े गर्व के साथ दावे करते हैं कि आजादी के बाद से भारत ने किस तरह तरक्की की है, लेकिन जब बात असम की आती है तो देश मानकर चलता है कि इस राज्य को बाढ़ से नहीं बचा सकते । यह जीवन की ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर साल करना होता है । जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है जिन्दगी फिर पटरी पर आ जाती है ।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट कहती है कि असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हर वर्ष आते हैं जिनमें मोरीगांव, जोरहट, धुबरी, लखीमपुर, गोलाघाट, बारपेटा, धेमाजी, सोनितपुर, गोलपारा, बोंगाईगांव और दरांग आदि शामिल हैं । इसके अलावा लगभग 17.94 आबादी इस बाढ़ से पीड़ित होती है ।|

186 ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों ने अपने किनारों को तोड़कर राज्य के 35 जिलों में से 23 जिलों को बाढ़ से प्रभावित किया । करीब दो लाख हेक्टेयर में लगी फसलें डूब गयीं । इसकी वजह से लगभग 11 लाख लोग प्रभावित हुए । 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 1.5 लाख से ज्यादा लोग 460 से ज्यादा राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं ।

मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए जिससे नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने बाढ़ से बचाव के पारंपरिक तौर-तरीके विकसित किए जाएं । वह उन पर ही भरोसा करते हैं । तटबंधों के पास के सुरक्षित इलाकों में रह रहे लोगों को जरूर बाढ़ का पानी प्रभावित करता है ।

सरकार और संबंधित एजेंसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करें और बाढ़ के समय वाटर फिल्टरेशन और प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी

का कोई प्रावधान लाए और मजबूत बांधों को बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाए ।